



:: आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN-20221164SX000000B95C

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश संख्या / OIO No.	दिनांक / Date
	V2/29/RAJ/2022	51 & 52/JC(MAN)/2021-22	10-02-2022

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-371-2022

आदेश का दिनांक /
Date of Order: **28.11.2022** जारी करने की तारीख /
Date of issue: **28.11.2022**

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s. Shree Ram Borewell (Prop. Rajnikant Bhikhabhai Patel), Office No. 20,
Ajanta Commercial Complex, Gondal Road, Opp. Sadhna Bhel, Rajkot**

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following
way.

(A) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के
अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section
86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) बर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं. 2,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New
Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बहाए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की
पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor,
Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- (a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए
गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और
लाघा गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये,
5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक
रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के
साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of
Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be
accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty
demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of
crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where
the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.
Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवानी, 1994, के नियम 9(1) के तहत
निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से
एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लाघा गया जुर्माना, रुपए 5
लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा
10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक
रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस
शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए
का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed
in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be
accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be
accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is
more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest
demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the
Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is
situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (iii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - सेनबेट जमा की ली गई गलत राशि
 - सेनबेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होये। /
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयापेक्षा निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमप्रवृत्तक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
 - भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
 - यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
 - सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
 - उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
 - पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
यहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
 - यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ङग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
 - यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
 - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में बर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
 - उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbcc.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbcc.gov.in

(Handwritten signature)

अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL

M/s Shree Ram Borewell (Prop. Rajnikant Bhikhabhai Patel), Office No.20, Ajantha Commercial Complex, Gondal Road, Opp. Sadhna Bhel, Rajkot-360 001 (hereinafter referred to as the appellant) has filed appeal No.29/RAJ/2022 against Order-in-Original No. 51 & 52/JC (MAN)/2021-22 dated 10.02.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Joint Commissioner, Central Excise & CGST, Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. Facts of the case, in brief, are that as per data received from the Income Tax department, the appellant appeared to have received various amounts as consideration for providing taxable service during the period 2014-15 and 2016-17. It appeared that the appellant had not obtained Service tax registration and did not pay service tax. Therefore, two show cause notices No.V.ST/Div-I-RJT/JC/AS/76/2020-21 and No.V.ST/Div-II-RJT/JC/AS/81/2020-21 both dated 29.09.2020 were issued to the appellant demanding service tax of Rs.81,26,508/- and proposing penalty under Sections 77 and 78 of the Finance Act, 1994. The adjudicating authority, by the impugned order, had confirmed the demand of Rs.6,01,748/- along with interest under Section 75 of the Finance Act 1994 and dropped demand of Rs.75,24,760/-. The adjudicating authority imposed penalty of Rs.6,01,748/- under Section 78 of the Finance Act 1994, Rs.10,000/- under Section 77(1)(a) and Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994. The show cause notice No.V.ST/Div-II-RJT/JC/AS/76/2020-21 was dropped.

3. Being aggrieved, the appellant filed the appeal wherein they, *inter alia*, contended that the adjudicating authority erred in invoking extended period of limitation as he failed to discharge onus of establishing presence of ingredients necessary to invoke extended period of time under Section 7391) of the Finance Act, 1994. The appellant submitted that the adjudicating authority erred in holding that the machine used for drilling water is not agriculture machinery and hence cannot be considered as service for agriculture purpose. The appellant contended that department has specifically kept out the service drilling and boring out of service tax net vide notification No.15/2005-ST dated 07.06.2005. The appellant submitted that basic ingredients which are required to attract penalty under Section 78 of the Finance Act, 1994 are missing in present case and hence imposing penalty is illegal.

4. Shri Divyesh Bhaptani, Chartered Accountant appeared for personal on 11.11.2022 and reiterated the submissions made in the appeal and



[Handwritten signature]

those in the written submissions handed over during the personal hearing. He submitted that the appellant's activity of drilling bore-wells in agricultural fields is under the negative list under Section 66D(d)(i) and the same was specifically excluded from purview of service tax vide Notification No.15/2005-ST even before introduction of the negative list in 2012. In fact Central Government is extending financial assistance to the extent of 100% of the cost limited to Rs.30,000/- in each case for this activity. Further, in the matter of interpretation regarding taxability or otherwise of a service, suppression or fraud cannot be alleged. Therefore, extended period cannot be invoked for show cause notice. Further, the show cause notice issued on 29.09.2020 is beyond five years of extended period in respect of F.Y. 2014-15. Therefore, he requested to set aside the order-in-original and allow the appeal.

4.1 In the written submissions made at the time of personal hearing, the appellant submitted that the show cause notices issued invoking extended period is illegal as the same have been issued only on the basis of Form No.26AS supplied by the income tax department. They contended that show cause notices issued on 29.09.2020 are time barred under Section 73 of the Finance Act, 1994. They contended that demand raised on service rendered to agriculturist is nothing but difference of opinion and it cannot be considered as fraud or collusion or wilful misstatement. They relied upon in the case laws of *Cosmic Dye Chemical-1995 (75) ELT.721 (SC)*, *Simplex Infrastructure Ltd-2016 (42) STR.634*, *Steel Cast Ltd-2011 (21) STR.500*.

4.2 The appellant submitted that service rendered to agriculturists is falling under Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994 as it is directly related to agriculture produce as they have rendered the service of boring to get the ground water to be used in agriculture activity.

4.3 The appellant submitted that after reducing the service rendered to the Governments, agriculturists and charitable institutions, the total services rendered were below threshold limit of exemption prescribed and the appellant was not required to register for service tax.

4.4 The appellant contended that case laws cited by the adjudicating authority are irrelevant. They also submitted that penalty imposed is unwarranted.

5.1 I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal in the appeal memorandum. The issue to be decided is whether the service of drilling bore-wells for agriculturist is exempted from service under Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994 or otherwise. Section 66D(d) of the Finance Act, 1994 reads as under:

"(d) services relating to agriculture or agricultural produce by way of—

- (i) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;
- (ii) supply of farm labour;
- (iii) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;
- (iv) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;
- (v) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;
- (vi) agricultural extension services;
- (vii) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce"

5.2 Plain reading of the above provision would reveal that it covers services relating to agriculture or agricultural produce by way of agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing. Drilling of borewell, in my view, can be considered as an agricultural operation directly related to production of agricultural produce. Irrigation is essential for cultivation of any crop and, therefore, drilling of well is to be considered as an agricultural operation. The reliance taken by the adjudicating authority in the Advance Ruling No.AAAR/14/2021 (AR) dated 30.06.2021 issued by Tamilnadu State Appellate Authority is on the wrong footing as the same was rendered in the GST era and cannot be made applicable to Service Tax Matter. I also find that in the said Advance Ruling as reported at **2021 (54) G.S.T.L. 408 (App. A.A.R. - GST - T.N.) in TVL. Vallalar Borewells**, the said party has contend before the Appellate Authority for Advance Ruling as under:

"The Hon'ble Finance Minister vide TRU Letter No. F. No. 354/35/2014-TRU, dated 4-3-2014 has clarified that drilling of borewell for supply of water for production of any agricultural produce is excluded from service tax since it is covered by the scope of negative list entry in Section 66D(d)(i) of the Finance Act."

5.3 It was in this context the Appellate Authority for Advance Ruling observed as under:

"7.5 The letter of the then FM quoted and relied by the appellant was also discussed by the Fitment Committee and finds mention during the 28th GST Council Meeting vide Annexure IV to agenda Item 7. After deliberations, the Council approved the proposal of Fitment Committee of not acceding to the demand of exemption for drilling of borewells for agriculture from GST but required to study further. In the same table in Annexure IV pertaining to issues relating to services, against Sl. No. 3 (page No. 258 of Vol. I), the Fitment Committee while stating that the same issue was already raised in the service tax regime quoting the FM letter, further reasoned as "The services covered by the scope of Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994 and Sl. No. 25(a) of the mega exemption Notification No. 25/2012-S.T. are exempted in GST vide Sl. No. 54 and 3 of Notification No. 12/2017-C.T. (Rate). Thus, the status quo has been maintained in GST vis-a-vis Service



Handwritten signature

Tax regime". It is clear from the above that as such no exemption was intended by the Government for borewell drilling for agricultural purposes and continues to be under its examination."

6. From the above, it is evident that by Letter No. F. No. 354/35/2014-TRU, dated 4-3-2014 of the Finance Minister has clarified that drilling of borewell for supply of water for production of any agricultural produce is excluded from service tax since it is covered by the scope of negative list entry in Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994. As I already observed, the above Advance Ruling given was in the matter of GST based on the decision of GST Council and the same cannot be made applicable to matter related to taxation of Service Tax. As such, I hold that demand of service tax on the service of drilling of borewell to agriculturalist is not sustainable. I find that the value of taxable service provided by the appellant, after deducting the exempted services, is below the threshold of 10 lakhs as provided under Notification No.33/2012 dated 20.06.2012 and hence no demand of service tax arises. Thus the entire demand of service tax becomes not sustainable and hence there arises no question of imposing any penalty.

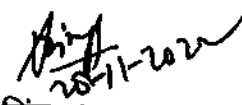
7. In view of the above discussions and findings, I set aside the demand of service tax amounting to Rs.6,01,748/- and penalties imposed under Sections 77(1)(a), 77(2) and 78 of the Finance Act, 1994.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

8. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above

सत्यापित / Attested


Superintendent
Central GST (Appeals)
Rajkot


(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH)
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में, मे० श्री राम बोरवेल (प्रोप रजनीकान्त भिखभाई पटेल) ऑफिस नुं 20, अजंता कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओप्प। साधना भेल, गोंडल रोड राजकोट-360 001.	To M/s Shree Ram Borewell (Prop. Rajnikant Bhikhabhai Patel), Office No.20, Ajantha Commercial Complex, Opp. Sadhna Bhel, Gondal Road, Rajkot-360 001
--	--

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रमंडल-1, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।